किसी सदस्य के सवाल पूछने को नहीं रोका जा सकता ।

श्री उग्रसेन : माननीय उपाध्यक्ष जी, मास्को, रूस में विदेशी भाषाओं खास करके एशियाई भाषाओं का खोज की जो इंस्टीच्यूट है वह विदेशों की कुछ प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद करके छपवाता है भारत की भी गीता, महाभारत और कन्नड़ भाषा की राजतरंगिणी का अनुवाद करके उन्होंने छपवाया है । मैं प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो रूसी साहित्य है उसमें भी अच्छी अच्छी बातें होंगी, उन पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराकर भारतीय दूतावासों के माध्यम से विदेशों में उसको वितरित कराया जाए ?

श्री मोरारजी देसाई : यहां अनुवाद करके वहां बंटवाना, मेरी समझ में नहीं आता । अगर हिन्दुस्तान में बंटवाने का सवाल हो तो यहां का साहित्य इतना सम्पूर्ण है कि दूसरों के साहित्य की हमें जरूरत नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही नहीं है कि तमाम दूतावास अपना साहित्य छपवा कर भारत में बंटवाते हैं ? क्या इससे इन्कार किया जा सकता है ? क्या हमारे साहित्य को भी विदेशी भाषाओं में छपवाकर भारतीय दूतावासों के माध्यम से विदेशों में बंटवाने की कोई योजना है ? पिछली सरकार ने जो कर्म किये, और अब जो भारत की तस्वीर है, उसका उल्लेख करते हुए क्या किसी साहित्य को विदेशों में बंटवाने की आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : हम अपना झगड़ा बाहर नहीं ले जाना चाहते ।

चौधरी बलबीर सिंह : प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम किसी की स्वतंत्रता में दखल नहीं दे सकते, तो यह बड़ी हैरानी की बात है कि मुल्क की सिक्योरिटी के मसले में हम दखल न दें । हिन्दुस्तान में सोवियत लैंड और दूसरे रिसाले आते हैं और बिकते हैं, और कम कीमत कर बिकते हैं, और उसका पैसा वापस नहीं जाता है । वह रुपया वापिस नहीं जाता है यह रह जाता है और यहां वह दे दिया जाता है । इसके बारे में अखबारों में छप चुका है और मेरा ख्याल है कि एक बार सरकार ने जवाब भी दिया था कि यह पैसा यहीं रहता है और जाता नहीं है । बाहर के मुल्क वाले जो यहां लिट्रेचर बेच कर और यहां की एक पोलिटिकल पार्टी को पैसा दे देते हैं, इसको रोकने में क्यों सरकार असमर्थ रहती है, इसके रास्ते में कौन सी रुकावट है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका जवाब दे दिया गया है ।

Integrated Medical Graduates

*468. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether 8th Executive Meeting of Central Council of Indian Medicine on the 10th February, 1973 approved the eligibility of integrated medical graduates to perform major operations and decided that a list of such institutions should be drawn up whose graduates could enjoy the right; and

(b) if so, the reasons for not drawing up the said list so far?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) "एकीकृत चिकित्सा स्नातक" शब्द का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट न होने के कारण यह सूची तैयार नहीं की जा सकी क्योंकि भारतीय और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का एकीकरण अभी नहीं हुआ है वैसे, 3 मार्च, 1977 को हुई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की 7वीं बैठक में यह निर्णय किया गया है कि

भारतीय चिकित्सा की जिन संस्थाओं और अर्हताओं के पाठ्यक्रमों में बड़े आपरेशन करने के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है, उनकी एक सूची तत्काल तैयार की जाए और उसे अन्तिम रूप देने से पहले परिषद् के सभी सदस्यों को उनके विचार जानने के लिए भेजा जाए।

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : यह जो सूची तैयार की जाती है इसको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जाएगा ?

श्री राज नारायण : अन्तिम स्वरूप देने का प्रश्न वास्तव में बड़ा जटिल प्रश्न है। हमारे यहां एक भारतीय चिकित्सा परिषद् है और उसके 82 सदस्य हैं और श्री शिव शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं। यह विवाद आज का नहीं है। यह विवाद आज सारे देश में खड़ा हुआ है कि आयुर्वेद और यूनानी और एलोपैथी इन दोनों का इंटग्रेटिड कोर्स चले, दोनों को एक में मिला करके चले या दोनों अलग अलग रहें। यह विषय आज से नहीं 1920 से चला हुआ है। राज्य सरकारें भी फैसला लेती हैं, केन्द्रीय सरकार भी समय समय पर कोई समिति बना करके निर्णय लेने पर विचार करती रही है। अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी की सम्मति है और हमारी अपनी भी सम्मति है कि आयुर्वेद की शिक्षा शुद्ध रूप से अलग रूप से, पथ्क करके दी जाए ताकि आयुर्वेद क्या है समुचित रूप से हमारे देश के लोगों को जानकारी हो सके, होम्योपैथी क्या उसकी पथक से ठीक से अलग से जानकारी हो सके, यूनानी पद्धति की भी जानकारी ठीक रूप से हो और इनको एलोपैथी के साथ मिला करके, तालमेल करने से कोई बड़ा भारी हित नहीं हुआ है। जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीय जीतने के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया उसी तरह से चिकित्सा पद्धति को भी प्रभावित किया (व्यवधान) ... अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। सुनना चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं।

यह एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। आज हम भी दो घन्टे तक अपने सचिवों के साथ बात कर रहे थे। आयुर्वेद में शल्य प्रथा थी या नहीं और आयुर्वेद के जानकारों को सर्जरी के मेजर आपरेशन करने की इजाजत दी जाए या नहीं ? यही तो पूरा सावल है आज। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं दी जाए, कुछ लोगों की सम्मति है कि दी जाए। और मैं यहां अगर आ कर स्पष्ट रूप से कहूं तो कल से बाहर घेराव शुरू होगा क्योंकि जो विद्यार्थी अब तक पढ़े हैं, अब एक सम्मति है कि अब तक इंटेग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई जिन्होंने की है उनको आपरेशन करने की इजाजत दी जाए। बाकी की राय यह है कि यह 82 सदस्यों की सम्मति आ जाए उसके बाद एक कोर्स तैयार हो गया है, उस कोर्स की समुचित पढ़ाई हो। उस पढ़ाई के बाद आगे क्या किया जाए उस पर विचार किया जाए तो उनको इजाजत दी जा सकती है। यह दोनों बातें हैं। हमारी अपनी निजी राय है और हमने प्रधान मंत्री जी की भी राय बता दी। जो लोग एलोपैथी के बड़े भारी समर्थक हैं वह भूलते हैं कि शंकर से बड़ा कोई भी सर्जन उनके यहां है जिन्होंने श्री गणेश के सर को काटा और हाथी का सर ला कर के लगा दिया ? मैं जानना चाहता हूं। यह एलोपैथी के सारे डाक्टर इसको खोजें। भारतीय इतिहास इसका साक्षी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की शिक्षा अलग हो। इंटेग्रेटिड कोर्स का विषय बड़ा व्यापक ह, इसकी शुद्ध परिभाषा हो। और मैं फिर श्री शर्मा जी को निवेदन करके बुलाऊंगा। उनकी भी यही राय है कि आयुर्वेद की पढ़ाई अलग हो। इंटेग्रेटिड कोर्स की एक साथ पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है।

श्री धर्म सिंह भाई पटेल : मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का एकीकरण कब किया जाएगा ?

श्री राज नारायण : मैंने पहले ही कह दिया इस पर कई कमिटियां बनी हुई हैं और वह अन्तिम राय तक पहुंचाने की अवधि तक पहुंच चुके हैं। मगर मैं पुन: इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं और लोगों को बुला रहा हूं कि सचमुच इंटेग्रेटेड कोर्स नाम की परिभाषा जो हुई है वह सही है या गलत है। मेरी राय में अब तक जो परिभाषा हुई है वह गलत है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे यह कहना है कि यदि हम प्रश्न-कर्ताओं को अपने प्रश्न पर कुछ अधिक कहने का अधिकार नहीं है तो उत्तर भी उतने ही संक्षेप में आना चाहिए। मैं शुद्ध आयुर्वेद का पक्षपाती हूं। मेरा यह कहना है कि क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि देश के स्वास्थ्य के हित में और एक रोगी के हित में जो एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति से ऊब कर दूसरी ओर जाता है उसको किसी खिचड़ी चिकित्सा पद्धति के सुपुर्द आप करने वाले हैं, या जैसी कि विशुद्ध चिकित्सा पद्धति वह चाहता है वह देने वाले हैं ?

श्री राज नारायण : मैं चाहता हूं कि वह विशुद्ध चिकित्सा पद्धति चाहे और हम उसको वही विशुद्ध चिकित्सा पद्धति दें।

SHRI O. V. ALAGESAN: I would like to bring to the notice of the hon. Minister that his Ministry's Annual Report has not yet been circulated to the Members. If it would have been circulated, we would have known more about this subject as also many other things. Will he kindly now circulate the Report at least today because otherwise tomorrow the Finance Bill will be discussed and we will be handicapped?

MR. DEPUTY SPEAKER: It is a suggestion, not a question.

श्री वेदव्रत वरुआ : जो लोग मैडिकल ग्रैजूएट होते हैं वह लोग शहर में चले जाते हैं, और पोस्ट ग्रैजुएट इंगलैंड चले जाते हैं। इसलिए चाइना में जैसा है कि बेयर फुट डाक्टर जो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद गांवों में काम करते हैं, तो क्या मंत्री जी उसी तरह से विशुद्ध डाक्टर हिन्दुस्तान में भी पैदा करेंगे जिससे वह जनता का काम कर सकें ?

श्री राज नारायण : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। मुझे अफसोस है कि उत्तर को समुचित न सुनने से पुन: प्रश्न किए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्यो-पैथी और नैचुरोपैथी आदि जितनी भारतीय पद्धतियां है, हम चाहते हैं कि ये विकसित हों और सस्ती से सस्ती दवाएं ग्रामीण और गरीब से गरीब जनता तक हम पहुंचायें। अभी तक स्थिति यह रही है कि हम शहरों की ओर देखते हैं, जितनी मैडिसन की बात हो रही है वह शहरों तक ही रही है, हमारी 82 फीसदी ग्रामीण जनता दवाओं से वंचित रही है। हमारा मंत्रालय चाहता है कि हम उनकी ओर पहले देखें जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। इसीलिए आयुर्वेद, यूनानी की सस्ती दवाएं बनाना, योग की साधना, नैचुरोपैथी, एलोपैथी, यूनानी सिखाना, इन बातों से सस्ती से सस्ती दवाएं बनाकर हम चलेंगे।

जहां तक एलोपैथी का जो अपना स्थान है, मैं निहायत अदब के साथ डाक्टरों और एलोपैथी के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि उनके महत्व को गिराना हमारा मकसद नहीं है, अनावश्यक ढंग से वे टैरीफाइड न हों। उनके महत्व को हम नहीं गिरायेंगे, उनको हम समुचित समादर देंगे, उनकी इज्जत करेंगे और उनसे यह भी चाहेंगे कि वे शहर मुखापेक्षी न होकर देहात की ओर ही देखें, उधर जायें और गरीबों की ओर ताकें। यह मैं उन से अपेक्षा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि हमारी अपील का असर हुआ है। जितनी जगहों पर मैं गया हूं, प्राइवेट प्रैक्टीशनरों से मिला हूं, वे इस बात पर राजी हुए हैं कि हम देहातों में फ्री मैडिसन बांटने के लिए तैयार हैं, सरकार हमारे लिए सवारी की व्यवस्था करे।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : पिछले 30 सालों में आयुर्वेद पर एक परसेंट भी खर्चा नहीं हुआ है। वह 1 परसेंट भी इन इन्टैग्रेटेड कोर्स के माध्यम से बाद में एलोपैथी पर ही खर्च किया गया। आयुर्वेद कालेजों से निकले हुए 99 फीसदी लोग एलोपैथी की ही प्रैक्टिस करते हैं, अपने नाम के आगे डाक्टर लगाते हैं, इससे आयुर्वेद तबाह हो रही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि शुद्ध आयुर्वेद चलाना चाहते हैं। पिछले 10 साल में हैल्थ काउंसिल और हैल्थ मिनिस्टरों की मीटिंग में यह तय हुआ है कि इन्टैग्रेटेड कोर्स आगे से बन्द किये जायेंगे, जो पढ़ चुके हैं, उनको सुविधा दी जायेगी ? वह कोर्स बन्द नहीं किये जा रहे हैं।

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब हैल्थ काउंसिल और हैल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में यूनैनिमसली तय हो गया कि यह पढ़ाई आगे न हो तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राज नारायण : मल्होत्रा साहब ने जो प्रश्न किया है, वह बिल्कुल ठीक है। आयुर्वेद और यूनानी पर अभी तक हमारे बजट का बहुत ही कम खर्च हुआ है, न के बराबर ही है। उसको मैं स्वीकार करता हूं। और उसके नाम पर जो खर्चा हुआ वह भी एलोपैथी पर चला गया।

मैं और प्रधान मंत्री जी निश्चित मत के हैं कि आयुर्वेद, यूनानी और दूसरी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों पर समुचित रूप से भारतीय बजट को खर्च किया जाये, उसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं।

|| पढ़ाई के लिए मैं बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे पार्लियामैंटरी अफेयर्स मंत्री जी ने बताया है कि साहब हमारे बजट पर गिलोटीन हो जाएगा, हमारे बजट के भाषण का गला कट जायेगा, तो अब मैं क्या करूं ? लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग एक कोर्स बना चुके है और अब चूंकि 9 राज्यों के नये-नये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, कुछ स्वास्थ्य मंत्रियों की ओर से पत्र आये हैं कि हम लोगों का एक सम्मेलन बुलाया जाए, तो हम एक सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं, तारीख भी 29 उसकी तय हो चुकी है। उस सम्मेलन में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और विशेषज्ञों के सामने तैयार किये गये कोर्स को रख देंगे। जो हमारा कोर्स है, उस पर करीब-करीब सब की सहमति हो चुकी है।

डा० कर्णसिंह : यह हमारा सौभाग्य है कि आज शंकर भगवान् जैसे सर्जन नहीं हैं, नहीं तो न जाने किस का सिर काट कर किस पर लगा देते। माननीय सदस्य, श्री मलहोत्रा, ने जो प्रश्न पूछा है, उस में दो सवाल मिल गए हैं। एक तो यह है कि भविष्य में जो शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, क्या उसमें एलोपैथी और आयुर्वेद इत्यादि का कोई सम्मिश्रण, इन्टैग्रेशन, होना चाहिए या नहीं। दूसरे, कुछ वर्ष पहले एक इनटेग्रेटिड कोर्स चला था। जहां तक मुझे स्मरण है, वह इनटेग्रेटिड कोर्स अब बन्द हो चुका है, नहीं चल रहा है। पहले तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या वह सो-काल्ड इनटेग्रेटिड कोर्स चल रहा है। मैं समझता था कि वह बन्द हो गया है, और जिन लोगों ने वह कोर्स पढ़ा है, केवल उनके प्रैक्टिस करने का प्रश्न है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या वह इनटेग्रेटिड कोर्स चल रहा है या बन्द है।

यह ठीक है कि हमारी सभ्यता अच्छे विचारों का सम्मिश्रण है—"आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः"। लेकिन जब हम सम्मिश्रण की ओर जायें, तो ऐसा भी न हो कि हमारी जो प्राचीन परम्परायें चली आ रही हैं, वे ऐसे ढंग से सम्मिश्रित हो जायं कि आयुर्वेद केवल निमित्त मात्र रखा जाए, और सारा प्रभाव एलोपैथी का हो जाए।

श्री राज नारायण : मुझे माननीय डा० कर्णसिंह को इस बात के लिए धन्यवाद देना

है कि जो बातें अभी तक प्रकाश में नहीं आई थीं, उन्होंने यह अवसर प्रदान किया कि मैं उन्हें प्रकाश में ला दूं । वास्तव में अभी साढ़े तीन महीने ही हुए हैं, जब से डा० कर्णसिंह स्वास्थ्य मंत्री नहीं हैं । भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री यह सवाल हम से पूछ रहे हैं, यद्यपि इस सवाल का उत्तर उन्हें अपनी ओर से देना चाहिए था कि इन्टेग्रेटिड कोर्स चल रहा है या नहीं, डा० कर्णसिंह ने उसे बन्द किया या नहीं । 1977-78 से सारे भारत में जो पाठ्यक्रम लागू हो रहा है, उसमें आयुर्वेद के शुद्ध स्वरूप पर ही विशेष बल दिया गया है । इन्टेग्रेटिड कोर्स डा० कर्णसिंह के स्वास्थ्य मंत्रित्वकाल से ही चल रहा है । भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के माध्यम से यह लागू किया गया है । हमने कहा है कि अब इन्टेग्रेटिड कोर्स मान्य नहीं होगा ।

डा० कर्णसिंह : वह चल रहा है या नहीं ?

श्री राज नारायण : वही तो मैं बता रहा हूं । एक्ट मेरे पास है । अगर इस एक्ट को पढ़ा जाये, तो मालूम होगा कि वह चल रहा है । मगर अभी हमने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, स्वास्थ्य सचिवों और आयुर्वेद के धुरंधर विद्वानों की जो बैठकें कीं, और श्री शिव शर्मा की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उन्होंने स्वतंत्र और शुद्ध रूप से यह विचार प्रकट किया है कि इन्टेग्रेडिट कोर्स को नहीं चलने देना चाहिए । अब हम उस पर पूरी तरह से अमल करने के लिए तैयार हैं । उस पर अभी सदन में चर्चा आयगी, और अच्छी तरह से विचार होगा । जैसा कि मैंने कहा है, हम 29 तारीख को बैठक बुला रहे हैं, जिसमें यह विचार किया जाएगा कि इस कार्यक्रम को किस तरह से लागू किया जाये । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अगर माननीय डा० कर्णसिंह के पास चिट्ठी न भी पहुंचे, तो भी वह 29 तारीख की बैठक में आ जायें ।

डा० सुशीला नायर : मैं मंत्री महोदय की सेवा में यह निवेदन करना चाहती हूं कि डा० कर्णसिंह के आने से भी बहुत पहले, 1967 से पहले, इन्टेग्रेटिड कोर्स को समाप्त कर दिया गया था, जब कि मेरा सम्बन्ध इस मंत्रालय से था, और शुद्ध आयुर्वेद का कोर्स बना दिया गया था । किन्तु शुद्ध आयुर्वेद के कालेजिज़ में पढ़ने वाले बहुत से विद्यार्थियों के बार-बार आग्रह पर राज्यों ने 1967 के बाद फिर अपने यहां कुछ-कुछ इन्टेग्रेशन का ही स्वरूप उस कोर्स को दोबारा दिया । तो माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि अब फिर, वह जब शुद्ध आयुर्वेद कोर्स करने जा रहें हैं, ऐसे आग्रह आने पर उन की क्या प्रतिक्रिया होगी, वह उस का क्या जवाब देने वाले हैं ?

श्री राज नारायण : मैं असल में उस समय गलतो कर गया, केवल डा० कर्ण सिंह जी का ही नाम लिया, मैं माननीय सदस्या को भी आमंत्रित करता हूं कि 29 तारीख की बैठक में वह भी आने की कृपा करें । डा० सुशीला नायर जी को आप लोग जानते हैं कि ये एक सम्मानित डाक्टर हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं तो इन की उपस्थिति से हम लाभान्वित होंगे । इन का कहना सही हैं, वही परेशानी हमारे लिए हैं कि बहुत से राज्य अभी तक पूर्ण-रूपेण इस चीज को नहीं मान रहे हैं । उन्हीं को मनाने के लिए बार बार उन की हम बैठक कर रहे हैं । एक बार मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की और फिर एक बार सचिवों को बुलाया है । जो नये चुनाव हुए हैं उस के बाद जो नये मंत्री बनें हैं वे आना चाहेंगे तो उन को भी बुला लेंगे और अपने पुराने अनुभवी स्वास्थ्य मंत्री जो रह चुके हैं, डा० कर्ण सिंह जी और डा० सुशीला नायर जी, इन को भी हम आमंत्रित किये देते हैं । इसके अतिरिक्त इस सदन के जो माननीय सदस्य वास्तव में कुछ देन दे सकते हों वे भी स्वतः आने की कृपा करें । मगर हम चाहते हैं कि आज देश में जो एक विचार खड़ा हुआ है वह विचार समुचित रूप से लोगों को ग्राह्य हो और लोग उस को मान लें ।

डा० सुशीला नायर ने यह बात सही

कही है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा, उन को शुद्ध कोर्स चलाने का आग्रह किया था परन्तु यह पूर्णतया सफल नहीं हुआ। उनका कहना सही है। डा० सुशीला नायर ने जो बात कही वह बिल्कुल ठीक कही। राज्य सरकारों ने नहीं माना। मैं खुद ही जानता हूं। हमारे यहां श्री सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री थे। वहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स को लेकर झगड़ा हुआ, हड़तालें हुईं, उन हड़तालों में हम लोगों ने विद्यार्थियों की तरफ से प्लीड किया मगर सम्पूर्णानन्द जी की भी वही राय थी जो कि हमारे प्रधान मंत्री जी की राय है और इन लोगों के चरणों में बैठ कर जो हम ने शिक्षा ली, हमारी भी अपनी वही राय है। अब जो यह लागू होगा वह अधिनियम के अन्तर्गत होगा और इसलिए राज्यों को उसे मानना ही होगा और इसलिए संसद् को एक अधिनियम इस के लिए पास करना होगा।

Conference on Mines' Safety

+

*469. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:
SHRI ANANT DAVE:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether a tripartite conference on mines' safety was held in New Delhi in the month of May, 1977;

(b) the persons who participated in the conference;

(c) the salient features of the recommendations or suggestions made in the conference; and

(d) whether Government have examined those recommendations or suggestions and if so, the decision taken by Government for implementing them?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) A tripartite meeting was held on the 18th May, 1977 to consider various aspects of safety in mines.

(b) A list is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT 696/77].

(c) and (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT 696/77].

श्री शंकरसिंह जी वघेला : अध्यक्ष महोदय, तीन बड़ी खान दुर्घटनाएं इस देश में हुई हैं—चासनाला, सुदामडीह और केसरगढ़ और वह प्रबन्धक इस के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने लापरवाही दिखाई, इतने पर भी सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिस से यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। अभी भी पता नहीं सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो स्टेप्स लेने चाहिएं वह लिए या नहीं जो उस के लिए जिम्मेदार थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खान दुर्घटनाओं में जो मारे जाने वाले श्रमिक थे, उन श्रमिकों को उपयुक्त मुआवजा देने का कोई कानून है जैसे रेलवे और हवाई जहाज में है ? यदि है तो मरने वालों को क्षतिपूर्त्ति कैसे की जाएगी ?

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, the question was about the Conference on Mines Safety. The hon. Member has raised the question of the accidents that take place—the gruesome tragedy that took place in Chasnala and other mines. Unfortunately, perhaps, the hon. Member was not present during the debates under the Demands of the Labour Ministry when, in fact, to question, it was stated in this House that the reports had been laid on the Table of the House. The Labour Ministry, the administrative ministry concerned as well as the ministries of the States concerned will look into and study the report and take appropriate action under different heads.

श्री शंकरसिंह जी वघेला : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब हर साल देश में तीन सौ लोग